आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 5.09.2022 से 10.00.2022)

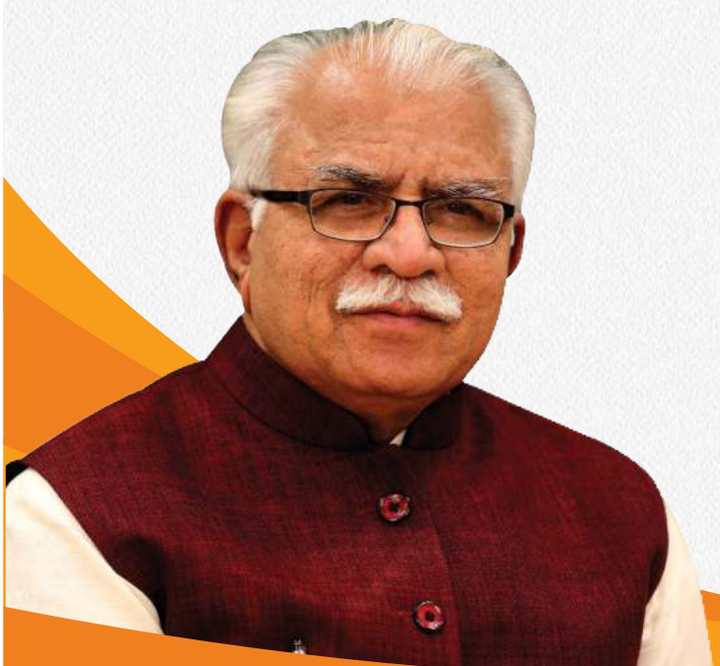

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

(दिनांक 06.09.2022)

विषयः एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब एसवाईएल के मामले को हल करने की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। मंगलवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर मतभेद समाप्त करने और समाधान के लिए प्रयास करे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसवाईएल हरियाणावासियों का हक है और वे इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा के लिए यह पानी अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ हमें यह पानी नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली हमसे अधिक पानी की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब इस मामले में एक टाइम लाइन तय होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। यह नहर न बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का अधिशेष, बिना चौनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक

(दिनांक 06.09.2022)

विषयः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक स्थल और सामाजिक व धर्मार्थ संस्थान बनाने पर प्लॉट की महज 20 प्रतिशत राशि देनी होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह छूट न केवल एससी वर्ग को दी गई है बल्कि अन्य वर्गों को भी छूट दी गई है । इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग–ए (बीसी–ए) की संस्था द्वारा यदि कोई धार्मिक स्थल और सामाजिक संस्थान बनाया जाता है तो उसे प्लॉट की कुल राशि का 30 प्रतिशत ही देना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग–बी (बीसी–बी) के अंतर्गत प्लॉट की कुल राशि का 40 प्रतिशत देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था या ट्रस्ट

साप्ताहिक सूचना पत्र

की कैटेगरी उस ट्रस्ट में शामिल संबंधित जाति के सदस्यों से तय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला और चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसासिटी बनाने की स्कीम के लिए मंजूरी दी। बैठक के दौरान प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक ने इससे संबंधित एजेंडा पेश किया, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री जी ने एचएसवीपी की बैठक में विवादों का समाधान योजना के अंतर्गत रिहायशी, व्यवसायिक, संस्थागत, सामाजिक व धार्मिक श्रेणी के पुराने बकाया विस्तार शुल्क (म•जमदजपवद मिमे) को एकमुश्त देने के लिए 31.12.2022 तक नई पॉलिसी की घोषणा की। यह बताना उचित होगा कि जो सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाए अपना रेगुलर अलॉटमेंट लेटर प्राप्त नहीं कर पाई उनके लिए यह योजना लागू की गई है। इससे कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं लाभान्वित होंगी। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री जी ने एचएसवीपी को आनलाइन प्रणाली इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के 8300 प्लॉट धारक एलएफएसएस–2022 योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के 139 सेक्टर में 8300 प्लॉट धारकों द्वारा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए शुभकामनाएं दी। इस योजना में एचएसवीपी 800 करोड़ रुपये की छूट प्लॉट धारकों को देगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा

(दिनांक 06.09.2022)

विषयः हरियाणा में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा।

प्रभावः नागरिकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार भिवानी जिले में बवानीखेड़ा, गुरुग्राम जिले में मानेसर, जींद जिले में जुलाना, करनाल जिले में नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी, पानीपत जिले में इसराना, रोहतक जिले में कलानौर और यमुनानगर जिले में छछरौली को उपमंडल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने इन क्षेत्रों के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपमंडल सरकार और प्रशासन को लोगों के करीब लाएंगे तथा सुशासन के मूलमंत्र को सिद्ध करने में सहायक होंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

आयुष्मान भारत योजना के संबंध में बैठक

(दिनांक 07.09.2022)

विषयः आयुष्मान भारत योजना के संबंध में बैठक ।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र से लिंक करने के कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के लिए 1. 80 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। इसी प्रकार, 1.80 लाख रुपये से ऊपर की आय की श्रेणी सीमा को भी निर्धारित की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की संख्या 15.50 लाख परिवार है। हरियाणा सरकार के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा पीपीपी में पंजीकृत 25.85 लाख परिवारों का सत्यापित डाटा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 60रू40 अनुपात का खर्च वहन की भागीदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्राधिकरण ने आयुष्मान कार्ड पर राज्य सरकार को अपना लोगो लगाने की अनुमति प्रदान की है। इस बात की जानकारी दी गई कि आयुष्मान अस्पताल ने 519 प्राइवेट व 174 नागरिक अस्पतालों को शामिल किया है। इसी प्रकार 28,78,429 कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा 9,33,489 आयुष्मान परिवारों की पहचान की गई है और लगभग 539 करोड़ रुपये की राशि का क्लेम अब तक दिया जा चुका है। आयुष्मान योजना के प्रीमियम के रूप में 186 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, विमुक्त घुमन्तु जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में शामिल लाभार्थियों, भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों, चौकीदार, लंबरदार, आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के आश्रितों, द्वितीय विश्वयुद्ध सैनिकों के आश्रितों, इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे परिवारों को, हिंदी आंदोलन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को शामिल करना प्रस्तावित है। इसके अलावा, दिव्यांगों को भी 3 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक

(दिनांक 08.09.2022)

विषयः प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अपराध पर अंकुश लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस नेतृत्व को संगठित अपराध के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने सहित अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण और अनुकूल कानून–व्यवस्था की स्थिति भी प्रदेश के विकास को गति देती है, क्योंकि यह जनता को अपनी पूंजी और ऊर्जा राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

मुख्यमंत्री जी ने सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारी गैंगस्टरों, बदमाशों और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार

साप्ताहिक सूचना पत्र

करते हुए लागू करने पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि पुलिस को बिना किसी दबाव के केवल कानून और जनहित से निर्देशित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि अपराधी में भय पैदा हो और कानून का पालन करने वाले नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत बने।

साइबर क्राइम की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय के साथ अपराध के तौर–तरीकों में भी बदलाव आया है। वर्तमान में साइबर क्राइम की काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। अपराधियों ने भी अपने मोडस ऑपरेंडी साइबर दुनिया के अनुरूप बना ली हैं। उन्होंने डीजीपी को आदेश दिए कि पुलिस के साइबर तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएं ताकि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साइबर अपराध को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी चलाये जायें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए सभी फील्ड पुलिस युनिटस व स्टेट नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो मिलकर बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखने और इस संबंध में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अपराध रोकथाम के अन्य क्षेत्रों जैसे गैंगस्टर, आतंकवाद, मोस्ट वांटेड अपराधी, साइबर अपराध, यातायात और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

हरियाणा पुलिस की प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की लगातार कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए फील्ड में अधिकतम पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मोस्ट वांटेड अपराधियों, उद्घोषित अपराधियों और बेल जंपर्स की गिरफ्तारी के साथ–साथ अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए ताकि राज्य में अपराध दर को और कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोनीपत में रोडवेज चालक की हत्या बेहद दुखद है। चालक के हत्यारों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। विभाग द्वारा चालक के परिवार को सहायता देने के निर्देश दे दिए गए हैं। मृतक ड्राइवर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी कही है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई करेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक

(दिनांक 08.09.2022)

विषयः भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक।

प्रभावः महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, जो भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक हरियाणा राजभवन में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें शिरकत की।

मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने से संबंधित एक सर्वे करवाया जाए, जिससे यह पता लग सके कि आज के समय में किस जिले में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग रेड क्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की भी जानकारी

साप्ताहिक सूचना पत्र

एक प्लेटफार्म पर एकत्रित करे।

उन्होंने कहा कि नशा आज समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिस पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कार्य में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। सभी अधिकारी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि युवा जल्दी नशे की गिरफ्त में आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेडक्रॉस सोसाइटी इत्यादि सभी हितधारकों को स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक करने पर जोर देना चाहिए और अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे महीने में एक बार अपने–अपने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेडक्रॉस सोसयटी को जहां कम–वहां हम की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवाभाव से कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी जिला अस्पतालों में फर्स्ट – ऐड की ट्रेनिंग के लिए एक विंग स्थापित की जाए, जिसके

साप्ताहिक सूचना पत्र

तहत रेडक्रॉस द्वारा दी जाने वाली फर्स्ट –एड की ट्रेनिंग इन विंग के माध्यम से प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर जिले के सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों और रेड क्रॉस या विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित एंबुलेंस की जानकारी दर्ज की जाए, जिससे लोगों को अलग–अलग माध्यमों की बजाय सिंगल प्लेटफॉर्म पर संपर्क करने की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिला उपायुक्त सीएमओ को निर्देश जारी करें कि वह अपने–अपने जिलों में अध्ययन कर यह पता लगाएं कि किन–किन स्थानों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता है। आमजन, विशेष तौर पर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है, ऐसे स्थानों पर इस प्रकार के केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें। इस अध्ययन के बाद आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि ब्लड डोनेशन के संबंध में एक पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर रेड क्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले ब्लड डोनेशन कैंपों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे यह पता लगेगा कि राज्य में वर्ष में कितने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं और कितना यूनिट ब्लड एकत्रित होता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सेंट जॉन एंबुलेंस द्वारा संचालित एंबुलेंस और ड्राइवर को स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा और अब इनका संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक कार्यों में सेवाभाव से योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए समर्पण पोर्टल विकसित किया है, जिस पर लगभग 5 हजार वॉलंटीयर्स ने अपना पंजीकरण करवाया है। रेडक्रॉस सोसायटी जिलों में अपनी गतिविधियों के लिए इन वॉलंटीयर्स का सहयोग लें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

छात्रा हीराक्षी के परिजनों से मुलाकात

(दिनांक 08.09.2022)

विषयः छात्रा हीराक्षी के परिजनों से मुलाकात।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने की घटना में जान गंवाने वाली छात्रा हीराक्षी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री जी ने सेक्टर 43 स्थित छात्रा के आवास पहुँच कर उनके परिवार से मुलाकात कर परिजनों का ढांढस बढ़ाया।

इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह से भी बातचीत की और उन्हें ऐसे प्रबंध करने के लिए भी कहा जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी इसी हादसे में घायल एक अन्य छात्रा इशिता के घर भी पहुँचे और छात्रा का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की । इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि छात्रा के आगे के इलाज में हर संभव मदद करेंगे।।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग जीतने पर बधाई

(दिनांक 09.09.2022)

विषयः नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग जीतने पर बधाई।

प्रभावः ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रचने पर मुख्यमंत्री जी ने पानीपत के रहने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई की आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और दुनियाभर में होने वाले खेल इवेंट्स में लट्ठ गाड़कर आते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पर देश और प्रदेश के युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेंगे और अपने–अपने खेल में पसीना बहाकर देश के लिए मेडल जीतने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे खिलाड़ियों की डाइट मनी हो या फिर प्रैक्टिस के लिए स्टेडियमों और अन्य चीजों की उपलब्धता, प्रदेश में सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि डायमंड लीग को ओलंपिक और विश्व चौंपियनशिप के बाद ट्रैक एंड फील्ड की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता माना जाता है। 2010 में शुरू हुए इस लीग के 13वें एडिशन में नीरज ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी पर भाला फेंक कर ज्यूरिख में भारत के लिए इतिहास रच दिया।

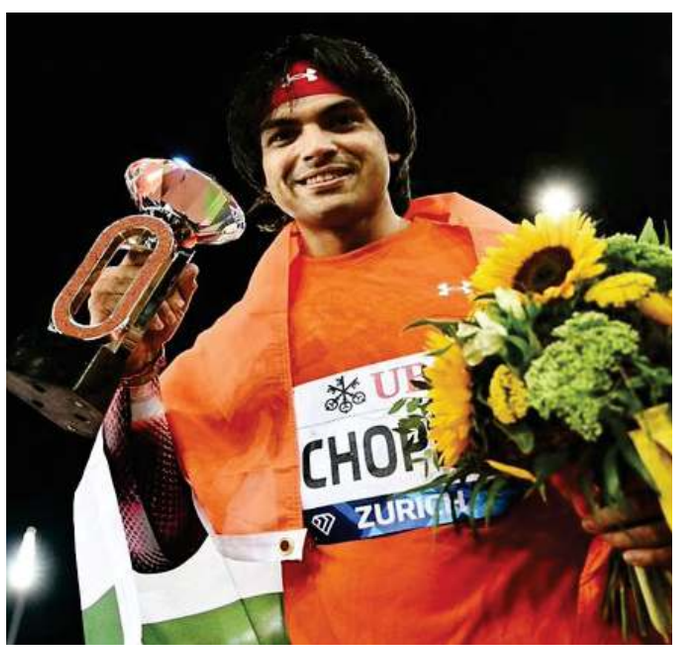

साप्ताहिक सूचना पत्र

नीट ऑल इंडिया टॉपर तनिष्का को बधाई एवं शुभकामनाएं

(दिनांक 09.09.2022)

विषयः नीट ऑल इंडिया टॉपर तनिष्का को बधाई एवं शुभकामनाएं।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर महेंद्रगढ़ निवासी तनिष्का से फोन पर बात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप करके आपने हरियाणा का मान बढ़ाया है। आप अच्छी डॉक्टर बन कर प्रदेश व देश के लोगों की सेवा करें यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

मुख्यमंत्री जी ने तनिष्का से कहा कि भविष्य में शिक्षा से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो सरकार को बताएं, हरियाणा सरकार हर कदम पर आपकी मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने तनिष्का के माता– पिता से भी बात की और उन्हें भी बेटी की इस उपलब्धि पर बधाई दी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा के साथ बैठक

(दिनांक 09.09.2022)

विषयः अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा के साथ बैठक।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा (उच्च शिक्षा संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक उपरांत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर और बेहतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा ने नई शिक्षा नीति – 2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रुप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में कुछ स्कूलों को विलय किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी आई है। केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती संस्थागत रूप से सुनिश्चित की गई है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है और वे इसका अनुसरण कर रहे हैं। इस नीति के तहत स्थानांतरित हुए अध्यापकों में से 90 प्रतिशत शिक्षकों को उनके द्वारा चुने हुए टॉप–3 विकल्प मिल रहे हैं और इससे शिक्षक संतुष्ट हैं। फिर भी यदि कहीं से शिक्षकों की कमी से संबंधित कोई मामले सरकार के समक्ष आ रहे हैं तो उन पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने महासंघ के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को समाज के साथ जोड़कर उनमे सेवा का भाव पैदा करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत सत्यापन, सर्वे या ऐसी अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों को अवश्य शामिल किया जाए।

बैठक में प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी मांगों को रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगों को मान लिया और कुछ मांगों पर

साप्ताहिक सूचना पत्र

विभाग के अधिकारियों को विचार–विमर्श करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। तदानुसार विषय वार तथा मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाएगी। इस नीति से विद्यार्थियों के साथ –साथ शिक्षकों को तो लाभ होगा ही और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।

बैठक में पदाधिकारियों द्वारा पीएचडी और एमफिल के लिए वेतनवृद्धि को मर्ज करने की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 1500 शिक्षकों की और भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा।

बैठक में पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा यूजीसी नियमों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारियों की शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों को निर्धारित समयावधि में निपटाएं। इसके अलावा, पहले से लंबित मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

''सफलता की कहानियाँ''नामक पुस्तिका का विमोचन

(दिनांक 09.09.2022)

विषयः ''सफलता की कहानियाँ'' नामक पुस्तिका का विमोचन।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी की पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर काम करने की सोच को आज एक बड़ी सफलता देखने को मिली जब मुख्यमंत्री जी की अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से स्वरोजगारी बने समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्तियों ने अपनी सफलता की कहानी अपनी ही जुबान से सुनाई।

मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के प्रभाव पर संकलित ''सफलता की कहानियाँ'' नामक पुस्तिका को विमोचित किया तो उनका कहना था कि यह पुस्तक गरीबी पर काबू पाने में अंत्योदय परिवारों के संघर्षों और चुनौतियों से पाठकों को अवगत करवाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कराहट लाना ही उनका राजनीति का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध

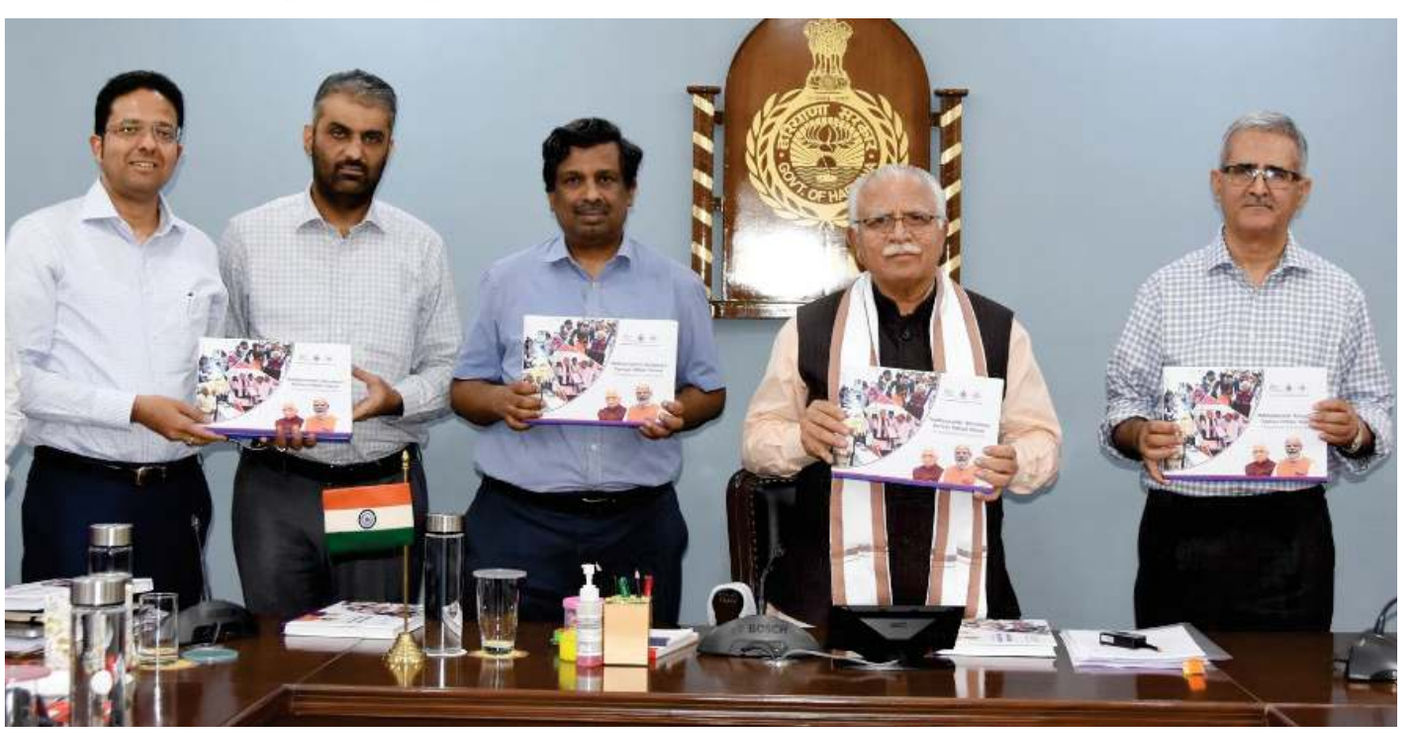

साप्ताहिक सूचना पत्र

आंकड़ों को सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा संकलित पुस्तक में योजना के लाभपात्रों की सफलता की कहानी में भिवानी की 19 वर्षीय मोनिका ने अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद एक छोटी डेयरी इकाई शुरू करके अपने परिवार की जिम्मेदारी ली। इसीप्रकार, बेरोजगारी से जूझ रहे अंबाला के अमनप्रीत ने अपना कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया और नौकरी तलाशने वाले से एंटरप्रेन्योर बन गए। यमुनानगर की एक विधवा, प्रवीण कुमारी ने अपने बच्चों का भरण–पोषण करने के लिए अपने घर पर ही सिलाई का कार्य शुरू किया।

इन सभी लोगों के बीच एक सामान्य बात यह है कि वे हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक अनूठी मिशन योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थी हैं। नवंबर 2021 से शुरू हुई इस योजना के अब जमीनी स्तर परिणाम आने लगे हैं। प्रदेश में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरू की गई। योजना के तहत वास्तविक जरूरतमंद व्यक्तियों ऋण प्रदान करने, कौशल–विकास और रोजगार सृजन योजनाओं से जोडकर उन्हें स्वरोजगारपरक बनाना है।

इस योजना की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से परिवार के समग्र उत्थान पर केंद्रित है। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 'अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों' का आयोजन है। इन मेलों के माध्यम से लाभार्थियों को विभागध्संगठन, बैंक और जिला प्रशासन द्वारा एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

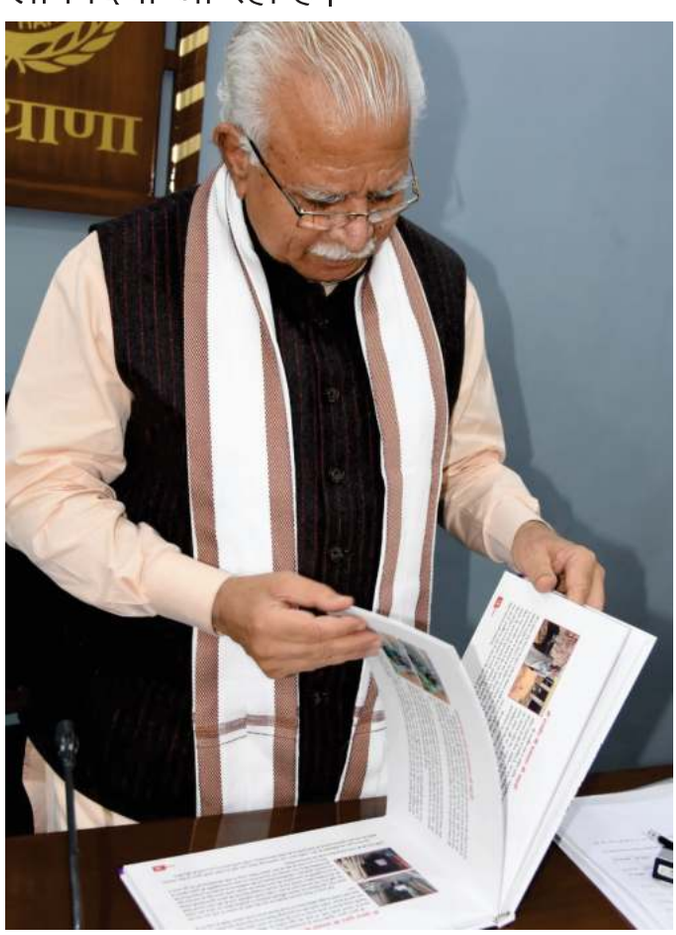

साप्ताहिक सूचना पत्र

बजट घोषणाओं पर समीक्षा बैठक

(दिनांक 09.09.2022)

विषयः बजट घोषणाओं पर समीक्षा बैठक।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जो पुराने पेड़ अंदर से खोखले हो गए हैं, विभाग तत्काल उनकी पहचान करे। इस संबंध में वन विभाग तत्काल प्रत्येक गांव और शहरों के वार्ड में सर्वे करवाए। ऐसे पेड़ों को चिन्हिंत करके अनुमति देकर उन्हें गिराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीते दिनों अंदर से खोखले हो चुके पेड़ गिरने की गई घटनाएं हो चुकी है। अगर ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर लिया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

खेल विभाग से जुड़ी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि खेल विभाग वर्तमान में जिन खेल नर्सरियों का संचालन कर रहा है वहां खिलाड़ियों की ऑनलाइन पोर्टल पर हाजिरी लगे और इस पोर्टल को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा

जाए। मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्टस विभाग को निर्देश दिए कि विभाग अपने खेल स्टेडियम की मरम्मत के लिए अपना इंजीनियरिंग विंग खड़ा करे, ताकि बेहतर तरीके से इन स्टेडियम का रखरखाव हो सके। उन्होंने कहा कि खेल विभाग पंचकूला की तरह गुरुग्राम में भी राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द से जल्द तैयार करे।

मुख्यमंत्री जी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि नगर दर्शन पोर्टल के तहत ऐसे कामों की सूची बनाई जाए जो प्राथमिकता के आधार पर किए जाने हैं। इन कामों की एक सूची जिलेवार और एक सूची पूरे प्रदेश के कामों की बनाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस सूची के आधार पर कार्य पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से जनता को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की मांग करने का अधिकार दिया है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने नगर दर्शन पोर्टल को एक प्रैक्टिकल पोर्टल बनाना है।

मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं कि अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए जल्द से जल्द लोन दिलवाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में जहां भी परेशानी आए उसे तत्काल दूर किया जाए। जिन बैंकों को लोन देना है, उनके अधिकारियों के साथ बातचीत की जाए और जल्द से जल्द जरुरतमंद लोगों के लिए लोन अप्रूव करवाए जाएं।

इसके साथ–साथ मछलीपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि संबंधित मछलीपालक इसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में विशेष ड्राइव चलाने के लिए कहा। इसके साथ–साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए तत्काल जमीन खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग ई–भूमि पोर्टल पर अपनी डिमांड डाले और जल्द से जल्द जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरा करे। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एक्वेरियम बनाए जाने के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए भी आदेश दिए।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

(दिनांक 09.09.2022)

विषयः ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया कि ज्यादातर शिक्षकों की ट्रांसफर की जा चुकी है। अब 8000 शिक्षकों की ट्रांसफर होना बाकि है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दो दिन के अंदर इन शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में ट्रांसफर ड्राइव की वजह से शिक्षकों की संख्या कम हुई है, उसे जल्द दूर किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी स्कूलों में जरूरत के हिसाब से शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो।

साप्ताहिक सूचना पत्र

राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल का दौरा

(दिनांक 10.09.2022)

विषयः राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल का दौरा।

प्रभावः मुख्यमंत्री जी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राखीगढ़ी में संरक्षित साइट की खुदाई के कार्य को तेज गति से पूरा किया जाए। साथ ही इन ऐतिहासिक साइट की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए ताकि कोई व्यक्ति इन साइट को नुकसान न पहुंचा पाए। हरियाणा सरकार की ओर से इस कार्य में हर संभव सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राखीगढ़ी का ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इन माउंड्स की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक से बात कर यहां पर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी अपनी ओर से प्राइवेट गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि संरक्षित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राखीगढ़ी के सभी 11 माउंड्स के लिए एक मास्टर

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक दीर्घकालीन पुनर्वास नीति तैयार की जाए। नीति बनाते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि ऐसे परिवारों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ उनके आजीविका के साधन भी सुनिश्चित हो। पुनर्वास के लिए स्थानीय विधायकों, पंच–सरपंचों के सहयोग से ग्रामीणों से बातचीत कर उनके लिए व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा होमस्टे नीति तैयार की गई है, जिसके तहत ग्रामीण अपने घरों में एक या दो कमरों का उपयोग टूरिस्ट के ठहराव के लिए कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से विधिवत लाइसेंस दिए जाएंगे। इस होमस्टे नीति से राखीगढ़ी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में होमस्टे कल्चर को प्रचलित करना

साप्ताहिक सूचना पत्र

है, ताकि एक और जहां स्थानीय लोगों को नया रोजगार मिले, वहीं टूरिस्ट को भी हरियाणा की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिले। उन्होंने टिक्कर ताल (मोरनी) का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर लगभग 30 परिवारों को होमस्टेट नीति के तहत लाइसेंस दिए गए हैं और वे उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राखीगढ़ी में खुदाई से मिली कलाकृतियों व अन्य पुरानी वस्तुओं की सूची तैयार करें। इसके अलावा, यदि ग्रामीणों के पास भी ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं तो उनकी भी एक सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से बातचीत कर इन कलाकृतियों को म्यूजियम में रखने की व्यवस्था की जाए और ग्रामीणों को बताएं कि म्यूजियम में कलाकृतियां देने वाले व्यक्ति का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा।

राखीगढ़ी में बन रहे म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लैब्स तैयार की गई है, जिनमें चित्रों के माध्यम से आगंतुक राखीगढ़ी के इतिहास को जान सकेंगे। इसके अलावा, म्यूजियम में किड्ज़ ज़ोन भी बनाया गया है। पहली बार हरियाणा में किसी म्यूजियम में किड्स जोन का निर्माण करवाया गया है ताकि ताकि बच्चे भी खेल खेल में अपने इतिहास से अवगत हो सकें। इसके अलावा, ओपन एयर थिएटर, गैलरी, पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे आगंतुक, विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिलेगी।

राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में स्थित है। यहां राखीखास और राखीशाहपुर गांवों के अलावा आसपास के खेतों में पुरातात्विक साक्ष्य फैले हुए हैं। राखीगढ़ी में सात टीले (आरजीआर–1 से लेकर आरजीआर–7) हैं। ये मिलकर बस्ती बनाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है।